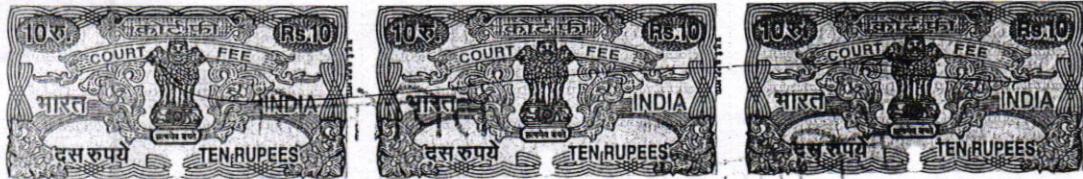


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प० ग्वा लियर ₹५०प०।



III। पुनर्बिलोकन। रीवा। भ्र० २०१७/८६७

१- मुसू- सुखराजुआ बिक्षा धर्म पत्ती स्व. लक्ष्मण प्रसाद उम्री लगभग 78

बर्ध।

२- श्रीमिथा प्रसाद तनय स्व. लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी उम्री लगभग 45 बर्ध।

३- बिधाकान्त चतुर्वेदी आत्मज स्व. लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी उम्री लगभग

४३ बर्ध -तीनो का पेसा कृषि एवं निवासीग्राम शुकुलगवां पो० ३० रतनगंगा

थाना व तहसील मउरँज, जिला रीवा ₹५०प०। -----आवेदकगण

बनाम

१- श्री ग्या प्रसाद चतुर्वेदी आत्मज स्व. रामकूमार चतुर्वेदी उम्री लगभग 5। बर्ध।

२- श्री राजधर तनय श्री राममनोहर ब्रा० उम्री लगभग 55 बर्ध।

३- श्रीमती कलावती धर्म पत्ती श्री राजधर ब्रा० उम्री लगभग 53 बर्ध

तीनो का पेसा कृषि एवं निवासीग्राम शुकुलगवां पो० ३० रतनगंगा

थाना व तहसील मउरँज, जिला रीवा ₹५०प०।

४- इसासनम०प० ----- अनावेदकगण

पुनर्बिलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५।

म०प० भू-राजस्व संहिता सन् १९५७ ई०।

पुनर्बिलोकन बिल्ड आदेश न्यायालय श्रीमान्

राजस्व मण्डल म०प० ग्वा लियर द्वारा प०५०/

आर-५११६-दो०/०१७ में पारित आदेश दि०-

२५.०५.०१७ ॥ पच्चीस मई सन् दो हजार

सत्रह

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त, जो बक्त तर्फ पेश किए जावेंगे, पुनर्बिलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित है :--

१- यह कि माननीय बिद्वान् न्यायालय द्वारा प०५०/आर-५११६-

12-10-17
H.S. 54
भारत सरकार
ग्राम पंचायती विभाग
मौजूदा नियमों का अधीन
प्रमाणित गया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—आ

प्रकरण क्रमांक तीन—पुनरावलोकन/रीवा/भू.रा./2017/3867

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	<p>राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5116—दो/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25—5—2017 पर से प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं।</p> <p>2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 25—5—17 के विरुद्ध पुनरावलोकन आवेदन 12—10—2017 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि आदेश दिनांक 25—5—17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदकगण ने दिनांक 4—9—17 को आवेदन दिया है एंव दिनांक 11—9—17 को आवेदकगण को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में म0प्र0 सँशोधन अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 से किये गये सँशोधन अनुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये 60 दिवस की समय—सीमा निर्धारित है। परिसीमा अधिनियम की धारा—5 के आवेदन में आवेदकगण ने बताया है कि दिनांक 25—4—17 को ग्राह्यता के बिन्दु पर बहस श्रवण करके प्रकरण आदेश हेतु सुनक्षित कर लिया गया और दिनांक 25—5—17 को आदेश पारित कर दिया। दिनांक 4—9—17 को आवेदक क्रमांक—3 ने ग्वालियर में अधिवक्तागण से जानकारी हासिल कर 4—9—17 को नकल का आवेदन पेश किया, उसके उपरांत पुनरावलोकन आवेदन दिया है।</p> <p>विचार योग्य है कि जब दिनांक 11—9—2017 को आदेश की</p>	

प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई, तब पुनरावलोकन प्रस्तुत करने के दिनांक 12-10-2017 अर्थात् एक माह का समय कहाँ व्यतीत हुआ, दिन-प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है।

1. स्टेट आफ एम०पी० विरुद्ध सवजीराम 1995 (2) म०प्र०वी०नो० 193 का न्याय दृष्टांत है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का न्याय दृष्टांत बीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म०प्र०ज० ल००ज० 45 में है।
2. लंगरी बनाम छोटा 1992 रा०नि० 289 (JLJ 69) में बताया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5- कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना - विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सदभाविक नहीं कहा जा सकता।

आदेश दिनांक 25-5-2017 के विरुद्ध पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 12-10-17 को प्रस्तुत किया गया है दिनांक 11-9-2017 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति के बाद दिनांक 12-10-2017 अर्थात् एक माह के विलम्ब का भी दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है, जिसके कारण अनुचित माफ करना संभव न होने से पुनरावलोकन आवेदन इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य